The issue price of levy sugar under the Public Distribution System during the last three years was as under :

Date from which effective	Retail price (Rs./Kg.)
1-1-1988	5·10
1-1-1989	5·25
24-7-1991 till date	6·10

चीनी का निर्यात

838. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1990–91 में देश में चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) क्या घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुये सरकार ने चीनी का निर्यात करने का निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किये जाने का विचार है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि आम मूल्य वृद्धि के कारण चीनी का उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे चीनी मिल मालिक वर्तमान चीनी नीति में परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) चीनी वर्ष 1990–91 (अक्तूबर से सितम्बर) के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन 119.05 लाख टन (अन्तिम) हुआ था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह निर्णय लिया गया था कि 1990–91 के मौसम के उत्पादन में से 5.61 लाख टन चीनी निर्यात की जायेगी ।

(ङ) मौजूदा चीनी नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

महाराष्ट्र में नये चीनी कारखानों को स्वीकृति दिया जाना

893. **श्री विश्वासराम रामराव पाटिल** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी कारखानों तथा उनका विस्तार किये जाने की स्वीकृति देने के लिये दस सदस्यों की एक नई समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो नये चीनी कारखानों के संबंध में समिति द्वारा कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ;

(ग) सरकार के पास महाराष्ट्र में नये चीनी कारखाने लगाने की स्वीकृति के लिये कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं, तथा उनकी प्राप्ति की तारीख, उन आवेदक कारखानों के नाम आदि का ब्यौरा क्या है जो मापदंड पूरा करते हैं; और

(घ) आवेदन पत्रों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के जारी हो जाने के परिणाम स्वरूप खाद्य मंत्रालय ने नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना तथा मौजूदा

फैक्टरियों में विस्तार के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये 10 सदस्यों की एक नई समिति गठित की है।

(ख) मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा लाइसेंस देने के लिये क्षमता की चरणबद्ध उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सामति लंबित आवेदन पत्रों की संवीक्षा करने के लिये समय समय पर अपनी बैठक बुलायेगी।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में 30-9-91 तक नई चीनी फैक्टरियों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु लंबित प्रस्तावों की सूची उपाबंध पर है। जांच समिति/लाइसेंसिंग समिति द्वारा इन आवेदन पत्रों की संशोधित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संवीक्षा की जायेगी।

[देखिये परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 16]

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में उत्तर दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालय

840. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये क्या मापदंड हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जो इन मापदंडों को पूरा करते हैं परन्तु वहां पर कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है; और

(ग) वहां पर कब तक ऐसे विद्यालयों के खोले जाने और उनके लिये भवन निर्माण कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) देश भर में प्राईमरी स्कूलों को खोलने के लिये कोई सख्त मानदंड नहीं बनाये गये हैं। केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि 300 की जनसंख्या (मरूस्थलीय, जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में 200) वाली सभी बस्तियों में एक-एक प्राईमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिये और सभी बच्चों को उनके निवास स्थान से एक कि०मी० की दूरी के अन्दर ही प्राईमरी शिक्षा की सुविधा व्यवस्था करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। प्रत्येक राज्य अपनी जरूरतों एवं नीति के अनुसार मानदंड निर्धारित करता है और प्राईमरी स्कूलों को खोलने और भवनों के निर्माण के संबंध में भी स्वयं ही निर्णय लेता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक की जनसंख्या वाली लगभग 14,300 बस्तियों में प्राईमरी स्कूल नहीं हैं।

Literacy rate in Arunachal Pradesh

841. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the present rate of literacy in Arunachal Pradesh, districtwise; and

(b) what steps Government have taken so far to increase the percentage of literacy in that States indicating the expenditure incurred for the purpose during the last two years?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) According to 1991 census, the provisional literacy rate in the state of Arunachal Pradesh for the population aged 7 years and above is 41.22%. The literacy rate for the districts of Arunachal Pradesh cannot be calculated till the popualtion in the age-group 0-6 is tabulated. However, the position regard-